पं० अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की अर्थनीति

डॉ. संगीता कुमारी *

सारांश :

पं० अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्ववाली राजग सरकार द्वारा जब सत्ता संभाली गयी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदारीकरण का दौड़ आरंभ हो चुका था। नरसिन्हा राव की सरकार ने उदारीकरण एवं आर्थिक ढाँचा को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठा चुके थे।

1980 में जब भाजपा का गठन हुआ, तो पं० अटल बिहारी वाजपेयी ने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में महात्मा गाँधी के न्यासिता के सिद्धांत को स्वीकार किया और कहा, समाजवाद और पूँजीवाद दोनों एक ही प्रकार की विषमता, अमानवीयता, हिंसा, स्वार्थ, लोभ, अनियंत्रित उपभोक्तावाद तथा अन्यताभाव (एलीनेशन) जैसी बुराइयों को जन्म देती है। गाँधी का न्यासिता का सिद्धांत संसार को तीसरा रास्ता दिखा सकता है।

पं० अटलजी ने स्वदेशी को स्पष्ट करते हुए कहा, स्वदेशी का अर्थ यह नहीं होता कि भारत आर्थिक क्षेत्र में विश्व से अलग खड़ा रहेगा। स्वदेशी का मतलब उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग और कड़े श्रम से आधुनिक और समृद्ध भारत बनाने का विश्वास जगाना है।

विदेशी पूँजी निवेश की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए कहा, सरकार नई औद्योगिक नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में पब्लिक सेक्टर में निजी पूँजी निवेश को आमंत्रित करने से पहले सरकार को पहल कर विपक्ष को विश्वास में लेने का आग्रह किया और कहा, वैसी सरकारी उद्यम, जो घाटे में चल रही है, उनका निजीककरण किया जाय और विदेशी पूँजी का उपयोग मूल उद्योग की स्थापना में लगाया जाय।

निजीकरण का मतलब सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों को निजी क्षेत्र में बेचकर उसकी भागीदारी बढ़ाना होता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की सहभागिता

***सहायक प्रोफैसर, राजनीति विज्ञान–विभाग, श्यामनन्दन सहाय महाविद्यालय, बीआरए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफरपुर**

को बढ़ाकर सार्वजनिक उपक्रमों की कमिया एवं विफलताओं पर सकारात्मक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पं० अटलजी की निजी आर्थिक मान्यता और उन पर गाँधी के न्यासिता सिद्धांत या पं० दीनदयालजी के एकात्म मानववाद का सिद्धांत का चाहे, जो भी प्रभाव रहा हो, राजनीतिक यथार्थताओं से वे अपने को पृथक नहीं कर पाये। उन्हें अपनी सिद्धांतों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में समायोजित होने के लिए बाध्य होना पड़ा।

मुख्य बिन्दु :

नवीन अर्थव्यवस्था का उदय, भारत में आर्थिक सुधार, भाजपा की अर्थनीति, पं. अटलजी सरकार की अर्थनीति एवं अर्थशास्त्रीय का सुधार।

उद्देश्य :

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में पं. अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान का अध्ययन किया गया है।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था पर पं. अटलजी के प्रभावों का वर्णन किया गया है।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर पं. अटलजी के भागीदारी पर चर्चा की गयी।

अध्ययन पद्धति एवं आँकड़ों का संग्रह :–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति एवं राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया। इसमें सामग्री का संग्रह प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्र, विभिन्न वेवसाइट एवं पुस्तकों के माध्यम से किया गया। इस अध्ययन की पद्धति वर्णनात्मक है।

परिचय :

पं० अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्ववाली राजग सरकार द्वारा जब सत्ता संभाली गयी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदारीकरण की दौड़ प्रारंभ हो चुकी थी। 1990 के दशक के आरंभ से भारत भी इस दौड़ में शामिल हो गया। पी० वी० नरसिन्हा राव के नेतृत्ववाली सरकार और तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिशा में गंभीरता से पहल प्रारंभ कर चुके थे। वह निजीकरण की राह को प्रशस्त की और भारतीय बाजार को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया।

इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी संकट ने भारत की नीति निर्माताओं की नयी आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया था। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरकण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था।

जिसमें राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सके। नई आर्थिक नीति की तीन प्रमुख घटक थे–उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

नवीन अर्थव्यवस्था का उदय : आर्थिक उदारीकरण का यह क्रम नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अतः पं० अटलजी सरकार की आर्थिक नीतियों के विश्लेषण करने से पहले यह आवश्यक है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्‌भव एवं विकास इसकी सामान्य अवधारणाओं का विश्लेषण किया जाय।

नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मूलतः ऐसी मान्यता है, जो समकालीन अर्थव्यवस्था को असंतोषप्रद मानते हुए, इसमें परिवर्तन का पक्षधर रहा है। इस प्रकार का मांग मूलतः युद्धोत्तर काल में नवोदित राज्यों के द्वारा प्रारंभ की गयी।

वास्तविक विश्व आर्थिक संकट 1929–33 में ही आरंभ हुआ। विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा इस दिशा में आपसी विचार विमर्श आरंभ हुआ, लेकिन कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सका। युद्धोत्तर काल में पारस्परिक वार्ता एवं समझौता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मोनेटरी फंड, विश्व बैंक और उसके बाद जेनरल ऐग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टेरिफ का गठन किया गया।

इस प्रकार एक विश्व व्यवस्था के निर्माण में पहल किया गया, जिसे कुछ विद्वानों ने उदार अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कतिपय व्यवस्थाएँ की गयी।

1960 एवं 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा विकास के लिए प्रथम एवं द्वितीय दशक में घोषणा की गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 77 विकासशील राज्यों द्वारा एक 'कौकस का निर्माण कर आर्थिक मामलों में बातचीत करने का एक समझौता 1964 में प्रथम 'अंकटाड' (UNCATED) के सम्मेलन में किया गया। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में उतर दक्षिण संवाद का काल प्रारंभ हुआ।[1]

विकासशील राज्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं राजनैतिक शक्ति संरचना में परिवर्तन की मांग कर भविष्य में समान विकास का अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाने लगा। इस संदर्भ में निरंतर वार्ताएँ चलती रही। अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सातवीं बैठक में विकसित राज्यों द्वारा कुछ सीमाओं के अंतर्गत नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मांग स्वीकार कर ली गयी। इस बात को स्वीकार किया गया कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था भेदभाव पूर्ण है। विकासशील राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पद्धति में समान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में क्रमबद्ध सुधार कर ही धीरे–धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।[2]

भारत में आर्थिक सुधार : भारत मूलतः 1991 में उदारीकरण की ओर अग्रसर हुआ। इसका मूल श्रेय नरसिन्हा राव सरकार और उसके वित्तमंत्री मनमोहन सिंह

को जाता है। यहीं से भारतवर्ष में आर्थिक क्षेत्र में नया युग आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत आर्थिक नीति में मौलिक परिवर्तन आरंभ हुआ। औद्योगिक नीतिगत प्रस्ताव को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया। कई औद्योगिक क्षेत्र, जो अबतक सरकारी नियंत्रण में थे, निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गये। नियंत्रणों को शिथिल किया गया तथा अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करके व्यवस्था को अधिक उदार बनाने का प्रयास आरंभ हुआ। इस उदारीकरण की प्रक्रिया का लक्ष्य था, विदेशी नियंत्रणों और विनिमय में कमी, 'फेरा' विदेशी विनिमय एवं नियमन अधिनियम में लचीलापन, व्यापार बाधाएँ खत्म करके मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देना और विदेशी निवेश में वृद्धि का प्रयास करना।[3]

भाजपा का अर्थनीति : 1980 में जब नये दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की गठन किया गया और उसके संस्थापक अध्यक्ष पं० अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो इनके द्वारा अपने अध्यक्षीय भाषण में गाँधीवादी आर्थिक सिद्धांत अपनाने की घोषणा की। उन्होंने महात्मा गाँधी के न्यासिता के सिद्धांत पर बल दिया और कहा, 'साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों ही एक नयी प्रकार की विषमता है, अमानवीयता, हिंसा, स्वार्थ, लोभ, अनियंत्रित उपभोगतावाद तथा अन्यताभाव (एलीनेशन) जैसी बुराईयों जन्म देती है। गाँधी की न्यासिता का सिद्धांत–संसार को तीसरा रास्ता दिखा सकता है। ट्रस्टीशिप का विचार पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के अच्छे तत्त्व ले सकते हैं।[4]

1990 वाली दशक में परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की मूल नीतियों में परिवर्तन के चिह्न दिखने लगा। इसके द्वारा एक तरफ जहाँ रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में स्वदेशी पर बल दिया गया, वही दूसरी तरफ शीतयुद्धोतर कालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में बाजार व्यवस्था की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया गया।

पं० अटलजी ने बार–बार आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी के अर्थ को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, स्वेदशी का अर्थ यह नहीं होता कि भारत आर्थिक क्षेत्र में विश्व से अलग खड़ा रहेगा। आर्थिक प्रौद्योगिकी और नये विचारों या निवेश को अनुमति प्रदान नहीं करेगा। स्वदेशी का मतलब उपलब्ध साधनों का अधिकाधिक उपयोग और कड़े श्रम से आधुनिक और समृद्ध भारत बनाने का विश्वास जगाना है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और प्रशिक्षित तकनीकी मानव श्रम हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय है।[5]

पं. अटलजी सरकार की अर्थनीति : पं० अटलजी ने 15 अगस्त 1998 को अपने उद्‌बोधन में कहा, भाजपा राष्ट्रीय विकास नीतियों के संदर्भ में दो प्रमुख पहलूओं का पक्षधर है। स्वराज का अर्थ परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्वराज

का अर्थ जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो स्वदेशी का अर्थ है, जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन के लिए अर्थतंत्र। आज विश्व आर्थिक क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो चुका है। हमें विश्व दर्जे का माल तैयार करना पड़ेगा, जो घरेलू एवं विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें कठोर परिश्रम, प्रमाणिकता और स्वाबलम्बन का मार्ग अपनाना होगा।[6]

उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, स्वदेशी का यह अर्थ नहीं कि हम विदेशी निवेश को महत्त्व न दे। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हमारे विकास के लिए जितनी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था हम स्वयं करें। घरेलू बचत को 26 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करने की ओर कार्य करने पर बल दिया और कहा, इन घरेलू संसाधनों की जरूरत को विदेशी संसाधनों से पूरा किया जा सकता है और पूरा करने की जरूरत है। इसमें संरचना विकास उच्च टेक्नोलॉजी बेहतर प्रबंध पद्धतियों का निर्यात क्षमता बढ़ाने हेतु उत्पादन की गुणवत्ता के उन्नयन एवं महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी बाजार संबंध जैसे विशेष प्राथमिता के क्षेत्र में विदेशी पूँजीवादी का स्वागत करने की बात की।[7]

जबकि 1991 में विपक्ष के नेता के रूप में बजट प्रस्ताव पर विचार में भाग लेते हुए पूँजी निवेश की अनिवार्यता को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार नई औद्योगिक नीति को लेकर आगे बढ़ रही है। इस दिशा में पब्लिक सेक्टर में निजी एवं पूँजी निवेश को आमंत्रित करने से पहले सरकार को पहल कर विपक्ष को विश्वास में लेने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी मांग किया कि भारतीयों की विदेशी पूँजी को भारत में वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वैसी सरकारी उद्यम, जो घाटे में चल रहे हैं, उनका निजीकरण किया जाय। विदेशी पूँजी का उपयोग मूल उद्योग की स्थापना में लगाया जाय।[8]

उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा, हम लघु उद्योग तथा भागीदारी के क्षेत्र पर अधिक व्यापक नीतिगत ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र स्वरोगार के महत्त्वपूर्ण स्रोत है।[9]

पं० अटलजी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के 1998 के वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आर्थिक विकास के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राजग सरकार के साझा कार्यक्रम 'विकास की वापसी', अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं रोजगार की ओर उद्योगपतियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, 'उनकी सरकार आर्थिक विकास को पूरी क्षमता के साथ प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत रहेगी। क्योंकि आर्थिक सुदृढ़ता पर देश की सुरक्षा अखण्डता और

स्थायित्व निर्भर करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी भी राष्ट्र का स्थान उसकी समृद्धि पर निर्भर करता है। भारत में आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण का प्रथम चरण 1991 में प्रारंभ हुआ, लेकिन आधारभूत विकास को अभी भी गति प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सुधार प्रक्रिया में आवश्यक सुधार लाया जाय।[10]

20 दिसम्बर 1998 को प्रधानमंत्री पं० अटलजी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के परिसंघ की वार्षिक आम बैठक में आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में उद्योग के दायित्व को बल दिया और कहा, आम लोगों की आवश्यकताओं एवं मांग सामान्य एवं बुनियादी किस्म की है। सभी जगहों पर लोगों को पानी, बिजली बेहतर सड़के, बेहतर अस्पताल और उन्हें रोजगार की आवश्यकता है। उनकी वैद्य एवं लोकतांत्रिक आवश्यकताओं की अब अनदेखी नहीं की जा सकती है।[11]

2000–2001 के वार्षिक बजट में 7 से 8 प्रतिशत रोजगार का अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ताकि अगले 10 वर्षों में बेरोजगारी समाप्त किया जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करना, ज्ञान आधारित उद्योग की विकास की क्षमता को बढ़ाना, कपड़ा, चमड़ा और कृषि प्रसंस्करण जैसे पारंपरिक उद्योग का आधुनिकीकरण, बुनियादी आधारभूत संरचनाओं की अड़चनों को दूर करने के निरंतर प्रयास, मानव संसाधन विकास को उच्च प्राथमिकता, तीव्र निर्यात वृद्धि, अधिक विदेशी निवेश और विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के जरिये विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय अनुशासन के लिए एक विश्वसनीय ढाँचा स्थापित करना शामिल होगा।[12]

अर्थशास्त्री का सुझाव :–भरत झुनझुनवाला पं० अटलजी सरकार को आर्थिक सुधार हेतु सुझाव दिया– (क) सरकारी निवेश में वृद्धि की जाय, चाहे कुछ महँगाई क्यों न बढ़े, (ख) सरकारी कर्मचारियों की कुशलता में सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए, (ग) राज्य स्तर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षाकर्मियों को न्याय और कानून व्यवस्था में लगाना तथा साथ साथ काम के बदले अनाज योजना लागू करना तथा (घ) निर्यातों की मात्रा बढ़ाने के स्थान पर पोर्टल बना कर निर्यातों का मूल्य बढ़ाना।[13]

इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम के अंधाधुन निजीकरण की दिशा में भी विचार किया जाना आवश्यक है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूँजी में निजी उपक्रमों एवं निवेशकों की सहभागिता बढ़ायी जाती है। दूसरे शब्दों में, निजीकरण का मतलब सार्वजनिक इकाईयों के

शेयरों को निजी क्षेत्र में बेचकर उसकी भागेदारी बढ़ाना होता है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाकर सार्वजनिक उपक्रमों की कमियाँ एवं विफलताओं पर सकारात्मक नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।[14]

पं० अटलजी और उनकी पार्टी अपने आर्थिक एजेंडे को क्रियान्वित करने की दिशा में वैश्वीकरण की दौड़ में प्रवेश कर गये। निजीकरण की प्रक्रिया आर्थिक उदारीकरण का अभिन्न अंग बन गया। ऐसी परिस्थिति में उनके गांधीवादी न्यासिता के सिद्धांत संबंधी मान्यता ऐतिहासिक महत्व की घटना बन गयी। दूसरा, आर्थिक राष्ट्रवाद की प्राप्ति किस प्रकार हो? विदेशी निवेश और विदेशी पूँजी पर निर्भर रहते हुए, आर्थिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना कम से कम उस समय तक मात्र सैद्धांतिक महत्त्व का प्रतीत होता है, जब तक भारत विश्व की एक महान आर्थिक शक्ति नहीं बन जाता है।[15]

पं० अटलजी ने सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा, सबसे पहली महत्त्वपूर्ण समस्या है, शहरी और ग्रामीण आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन लाना। इस दिशा में सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और ग्रामीण सड़क परियोजना का श्रीगणेश किया गया है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में बेहतर भागीदारी आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भूमिका राष्ट्रीय विकास में निरंतर तेजी से बढ़कर रहा है। उन्हें निजी लाभ के बजाय जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए।[16]

निष्कर्ष :

अन्त में यह कहा जा सकता है कि पं० अटलजी की निजी आर्थिक मान्यता और उन पर गाँधी के न्यासिता के सिद्धांत या पं० दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत का चाहे जो भी प्रभाव रहा है। राजनीति यथार्थताओं से वे अपने को पृथक् नहीं कर पाये। उन्होंने अपनी सिद्धांतों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में समायोजित होने को बाध्य होना पड़ा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. नितिन देसाई, नन एलयानमेंट एण्ड द न्यू इंटरनेशनल इकोनोमिक ऑर्डर, पी० के० घोष, न्यू इंटरनेशनल इकोनोमिक ऑर्डर (वाशिंगटन, 1984), पृष्ठ सं०–175–178
2. एस. अजीज, द इन्टरनेशनल ऑडर : सर्च फार कॉमन ग्राउंड (इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिव्यू खण्ड–20, 1978) पृष्ठ सं०–52
3. कम्पीटशन मास्टर, दिसम्बर 1994, पृष्ठ सं०–258
4. अध्यक्षीय भाषण, अटल बिहारी वाजपेयी, 1980–1986, भारतीय जनता पार्टी, 2000, पृष्ठ सं.–8

5. राधेश्याम गुप्त, निष्काम कर्मयोगी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्यय सेवा प्रकाशन लखनऊ 1999, पृष्ठ–178
6. 15 अगस्त 1998 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिला से संबोधन
7. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, विचार बिन्दु, (किताब घर, नई दिल्ली, 1999), पृष्ठ सं.–137
8. डॉ० ना० मा० घटाटे, अटल बिहारी वाजपेयी, संसद में तीन दशक, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992 पृष्ठ सं.–174
9. राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन 29 अप्रैल 1998 को दिया गया भाषण (विज्ञान एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2000)
10. भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 अप्रैल 1998 को नयी दिल्ली में दिया गया भाषण (सूचना प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2002)
11. 20 दिसम्बर 1999 नयी दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल परिसंघ फिक्की की वार्षिक बैठक में दिए गए भाषण (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली 2000)
12. केन्द्रीय बजट, 2000–2001, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2000
13. भरत झुनझुनवाला, वाजपेयी के लिए आर्थिक एजेण्डा, दैनिक जागरण, 19 सितम्बर 2001
14. अशोक कुमार सिंह, आर्थिक परिवेश में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का औचित्य, आज, 20 सितम्बर, 2002
15. द टाइम्स ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली, 17 सितम्बर 2002
16. अटल बिहारी वाजपेयी, नववर्ष का आह्वान, दैनिक जागरण, 3 जनवरी, 2001

****